नईदुनिया

संपादकीय

भाषा के नाम पर रोजगार पर ताला

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 20 अगस्त से उन ऑटो और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन्हें मराठी का कामचलाऊ ज्ञान नहीं है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर मराठी सीखने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी भाषा नहीं आई तो लाइसेंस और बैज निलंबित कर दिया जाएगा।

इस घोषणा के बाद देशभर में बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या भाषा के आधार पर रोजगार तय किया जा सकता है? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 19 में मिले मौलिक अधिकारों से टकराव नहीं है? और क्या कल को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य भी यही तर्क देकर दूसरे भाषाई राज्यों के लोगों को बाहर करने की मांग नहीं करेंगे?

इसमें कोई दो राय नहीं कि मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है और उसका सम्मान होना चाहिए। स्थानीय संस्कृति को बचाना और बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन सम्मान और बाध्यता में फर्क होता है। टैक्सी और ऑटो चालक लोगों से सीधे जुड़ते हैं। उनसे स्थानीय भाषा में संवाद की अपेक्षा सेवा की गुणवत्ता के लिए अच्छी बात है, लेकिन भाषा न आने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई रोजगार के अधिकार पर सवाल खड़ा करती है।

मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में लाखों लोग दूसरे राज्यों से आकर काम करते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत के लोग भी शामिल हैं। ये लोग वर्षों से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। भारत में हर नागरिक को देश में कहीं भी बसने और काम करने का अधिकार है। यदि एक राज्य भाषा के नाम पर दूसरे राज्यों के लोगों को काम से रोकने लगे तो यह राष्ट्रीय एकता की भावना के खिलाफ होगा। कल को कोई दूसरा राज्य भी ऐसी ही शर्त लगा सकता है।

व्यावहारिक दिक्कतें भी कम नहीं हैं। मुंबई जैसी महानगरी में हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषाएं चलती हैं। तीन महीने में भाषा सीखना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कम पढ़े-लिखे हैं। फिर भाषा की परीक्षा कौन लेगा और उसके मानक क्या होंगे, इसका स्पष्ट खाका भी सामने आना चाहिए।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऐसे नियम से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है। इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है और दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांगें उठ सकती हैं। इससे भाषाई दूरी बढ़ेगी, जबकि जरूरत देश को जोड़ने की है।

सरकार चाहे तो दंड के बजाय समन्वय का रास्ता अपना सकती है। मराठी सीखने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, परिवहन विभाग बुनियादी भाषा का पाठ्यक्रम चलाए और चालकों को आवश्यक वाक्यों की पुस्तिका दी जाए। मराठी सीखने वालों को प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है।

भाषा हमारे गर्व का विषय है, लेकिन उसे दीवार नहीं बनाना चाहिए। सरकार का इरादा यदि सेवा सुधार का है तो उसका स्वागत है, लेकिन यदि परिणाम रोजगार छीनना और देश को बांटना है तो यह खतरनाक होगा।

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का नारा तभी सार्थक होगा, जब हर राज्य अपने यहां आने वाले को अतिथि माने, बाहरी नहीं। महाराष्ट्र सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार कर भाषा सिखाने की व्यवस्था पर जोर देना चाहिए। देश तभी मजबूत होगा, जब हम भाषाई विविधता को अपनी ताकत मानेंगे, कमजोरी नहीं।

आजकल

एमपी में टीईटी की नई व्यवस्था

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पहली परीक्षा 12 अक्टूबर से शुरू होगी और फॉर्म 21 अगस्त से जमा होंगे। परीक्षा ऑनलाइन होगी और शिक्षकों को प्रति विषय एक हजार रुपए शुल्क देना पड़ेगा। टीईटी की रूल बुक देखकर शिक्षकों का पारा चढ़ गया है। शिक्षकों ने ऑनलाइन परीक्षा और शुल्क पर आपत्ति जताई है।

सर्वोच्च न्यायालय के सितंबर 2025 के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी 2026 की अनिवार्यता तय की है। मंडल की रूल बुक के अनुसार सेवारत शिक्षकों सहित सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रुपए प्रति प्रश्नपत्र परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को 50 प्रतिशत और अन्य वर्ग के शिक्षकों को 60 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। परीक्षा में दो पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर में 120 अंकों के प्रश्न होंगे।

शुल्क की दर सबसे बड़ी आपत्ति का कारण बनी है। दो पेपर देने वाले शिक्षक को दो हजार रुपए फीस देनी होगी। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह शुल्क बहुत अधिक है। सेवारत शिक्षकों से इतनी राशि लेना उचित नहीं है।

परीक्षा ऑनलाइन होना भी बड़ा मुद्दा है। मंडल का तर्क है कि इससे पारदर्शिता आएगी और नकल रुकेगी, लेकिन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, परीक्षा केंद्र की दूरी और तकनीकी जानकारी का अभाव परेशानी पैदा कर सकता है। कई शिक्षक लंबे समय से सेवा में हैं और कंप्यूटर का नियमित प्रयोग नहीं करते।

पात्रता परीक्षा का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है, लेकिन प्रक्रिया शिक्षकों के लिए बोझ नहीं बननी चाहिए। सरकार को सेवारत शिक्षकों के लिए शुल्क में राहत देने और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन विकल्प पर विचार करना चाहिए। तभी परीक्षा की प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक होगी।

पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव : ट्रंप की धमकी और ईरान का जवाब

वाशिंगटन से निकली एक खबर ने पूरे पश्चिम एशिया को फिर से हिला कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ओमान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान होर्मुज जलमार्ग के संचालन को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते के बीच में आया तो अमेरिका उस पर जबरदस्त बमबारी करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान और ओमान के बीच जलमार्ग के संचालन को लेकर बातचीत चल रही थी। अमेरिका को लगता है कि यह समझौता उसकी क्षेत्रीय रणनीति के खिलाफ है, इसलिए उसने ओमान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान को आत्मसमर्पण का सफेद झंडा लहराना चाहिए। उनके अनुसार, अमेरिका के पास कोई समय सीमा नहीं है और न ही उन्हें कोई जल्दी है। उनका मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न पहुंचे। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यावधि चुनावों से उनकी इस नीति का कोई लेना-देना नहीं है।

ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हटा। ईरानी सेना के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने घोषणा की है कि जो भी अमेरिकी सैनिक को मारेगा या पकड़ेगा, उसे ईरान की तरफ से 30 हजार डॉलर का इनाम दिया जाएगा और अगर यह काम कोई महिला करती है तो इनाम की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को उकसाने वाला माना जा रहा है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है।

ईरान का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ माना जा रहा है, लेकिन तेहरान इसे अपने आत्मसम्मान और संप्रभुता की रक्षा के रूप में देख रहा है। ईरानी मीडिया में इस घोषणा को देशभक्ति से जोड़कर पेश किया जा रहा है और जनता में इसका जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है।

होर्मुज जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ओमान और ईरान दोनों इस जलमार्ग के किनारे स्थित हैं और दोनों का इस पर नियंत्रण है। पिछले कुछ महीनों से खबरें थीं कि ईरान और ओमान मिलकर इस जलमार्ग के संचालन के लिए एक नया तंत्र बनाने वाले हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान इस

रास्ते का इस्तेमाल अपने हित में करेगा और अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर असर पड़ेगा।

इसी डर के कारण ट्रंप प्रशासन ने ओमान पर दबाव बनाना शुरू किया और जब बात नहीं बनी तो सीधी धमकी दे दी। विशेषज्ञ मानते हैं कि होर्मुज जलमार्ग को लेकर टकराव आने वाले समय में और बढ़ सकता है, क्योंकि यहां से तेल की आपूर्ति रुकने का मतलब होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर।

इसी बीच गाजा में रुकी हुई शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी निकोले म्लाडेनोव ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दल ने इजिप्ट में हमास के प्रमुख से भी बातचीत की, ताकि युद्धविराम और राहत सामग्री की आपूर्ति पर सहमति बन सके।

लेकिन जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। इजरायल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि गाजा में हर रात 30 से 40 लोगों को निशाना बनाना चाहिए। इस बयान के बाद फिलिस्तीनी पक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस तरह की सोच शांति प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर देगी।

पश्चिम एशिया का संकट सिर्फ ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक सैन्य जहाज पर हमला किया है। इस हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा है और कई सैनिकों के हताहत होने की खबर है। सऊदी अरब ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

हूती लगातार लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमले गाजा में हो रही बमबारी के विरोध में किए जा रहे हैं। लेकिन सऊदी और अमेरिका इसे ईरान की शह पर हो रही आतंकवादी गतिविधि मानते हैं।

ट्रंप प्रशासन एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ वह ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति अपना रहा है, तो दूसरी तरफ वह इजरायल के जरिए गाजा में शांति की बात भी कर रहा है। लेकिन दोनों नीतियों में तालमेल की कमी साफ दिख रही है। ट्रंप का ओमान को धमकाना इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब छोटे देशों को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, जो उसकी नीतियों से अलग रास्ता अपनाते हैं। लेकिन इस तरह की भाषा से क्षेत्रीय सहयोग कमजोर होता है और विरोधी ताकतों को एकजुट होने का मौका मिलता है।

भारत के लिए पश्चिम एशिया का यह संकट बेहद अहम है, क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी क्षेत्र से आता है। अगर होर्मुज जलमार्ग में कोई रुकावट आती है तो भारत में महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी चिंता का विषय है।

भारत सरकार ने अब तक संतुलित रुख अपनाया है। उसने शांति और संवाद की वकालत की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत को अपनी ऊर्जा और कूटनीतिक नीति में बदलाव करना पड़ सकता है।

फिलहाल हालात बहुत नाजुक हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ओमान ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि मस्कट में बेचैनी है। ईरान ने भी अपने बयान के बाद अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है।

गाजा में शांति वार्ता का भविष्य भी अनिश्चित है, क्योंकि इजरायल के अंदर ही इस मुद्दे पर मतभेद हैं और हमास किसी भी समझौते से पहले युद्धविराम और कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है।

यमन में हूती हमलों के कारण लाल सागर में जहाजों का आना-जाना पहले ही प्रभावित हुआ है और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा।

पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका की आक्रामक नीति, ईरान का जवाबी रवैया, इजरायल-फिलिस्तीन का अधूरा संघर्ष और यमन का गृहयुद्ध, सब मिलकर इस क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं।

डॉनल्ड ट्रंप का बयान केवल एक धमकी नहीं है। यह उस नई विश्व राजनीति का संकेत है, जहां ताकतवर देश छोटे देशों को सीधे आंख दिखा रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस तरह की धमकियों से समस्या सुलझती नहीं, बल्कि और गहरी होती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर बातचीत का रास्ता निकाले, नहीं तो होर्मुज से लेकर गाजा तक फैली यह आग पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकती है और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

शिक्षा का कत्ल, सरकार की नाकामी पर छात्रों की जीत

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आखिरकार झुकी और उसे छात्रों के आगे घुटने टेकने पड़े। 24 दिन तक सड़क पर बैठे छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार ने माना कि पिछले 12 साल से इस राज्य में परीक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। टीडीपीएल नाम की विवादित निजी एजेंसी के जरिए आयोजित की गई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं और 2014 से अब तक हुई हर छोटी-बड़ी गलती की जांच का आदेश भी देना पड़ा। यह फैसला अपने आप में झारखंड सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाणपत्र है।

सोचिए, एक सरकार जो खुद को गरीबों और युवाओं की हितैषी बताती है, वही सरकार 12 साल तक अपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रही। लाखों छात्रों ने मेहनत की, फीस भरी, फॉर्म भरे और अंत में पता चला कि पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ था। पेपर लीक, धांधली, मनमानी और निजी एजेंसी की मनमर्जी, यही झारखंड की भर्ती प्रक्रिया की सच्चाई बन गई थी।

सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार को अपनी गलती तब समझ आई, जब छात्र सड़कों पर उतर गए। जब दिल्ली में छात्र आंदोलन की गूंज रांची तक पहुंची, तब जाकर मुख्यमंत्री को होश आया कि राज्य में भी कुछ गड़बड़ है। इससे पहले सरकार और उसके अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि टीडीपीएल जैसी एजेंसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता था कि हर भर्ती में पेपर लीक और धांधली की शिकायतें आ रही हैं?

जवाब साफ है। सरकार को सब पता था, लेकिन वह आंखें बंद करके बैठी थी, क्योंकि इस पूरे गोरखधंधे में कई लोगों की जेबें भर रही थीं। निजी एजेंसी को ठेका देना मतलब सरकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और भ्रष्टाचार के लिए एक नया रास्ता खोल देना। हेमंत सरकार ने यही किया और अब जब पकड़ी गई तो जांच कमेटी बनाने का नाटक शुरू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री का बयान और भी हास्यास्पद है। उनका कहना है कि परीक्षा के लिए एसओपी बनी हुई थी। अगर उसका पालन होता तो गड़बड़ी नहीं होती। अरे मुख्यमंत्री जी, एसओपी बनाने के लिए नहीं, पालन करवाने के लिए होती है। अगर आपकी सरकार 12 साल तक एसओपी का पालन नहीं करवा सकी तो फिर आप सत्ता में किसलिए बैठे हैं?

आपने माना कि गड़बड़ी हुई है, आपने माना कि प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी है, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? 12 साल में कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ? कितने मेहनती बच्चों का हक मारा गया? क्या सरकार उनको नौकरी वापस देगी? क्या उन पैसों को वापस करेगी, जो छात्रों ने फॉर्म भरने में बर्बाद किए?

यह भी कम शर्म की बात नहीं है कि अपने राज्य की समस्या सुलझाने के लिए झारखंड सरकार को दिल्ली से पत्र का इंतजार करना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मुख्यमंत्री ने छात्रों से बात करने की जहमत उठाई। क्या राज्य की सरकार इतनी कमजोर और निष्क्रिय हो गई है कि उसे बाहर से याद दिलाना पड़े कि अपने राज्य के छात्र सड़कों पर हैं? हेमंत सरकार का फोकस शासन पर नहीं, राजनीति पर है। जब तक बाहर से दबाव नहीं आता, तब तक फाइलें नहीं चलतीं और जब आंदोलन तेज होता है तो आनन-फानन में फैसला लेकर वाहवाही लूटने की कोशिश की जाती है।

सरकार ने कहा है कि 2014 से हुई हर गलती की जांच होगी और एक आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। यह पुराना पैंतरा है। जब सरकार फंस जाती है तो जांच कमेटी बना देती है। सालों तक जांच चलती है और अंत में फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है। जांच कौन करेगा? उन्हीं अधिकारियों से, जो पिछले 12 साल से इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं? क्या वही अपनी ही नाकामी की जांच करेंगे? यह छात्रों के साथ एक और धोखा है। सरकार को चाहिए था कि तुरंत सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाती और दोषियों को जेल भेजा जाता। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया तो कई बड़े नाम सामने आ जाएंगे।

झारखंड एक युवा राज्य है। यहां हर साल लाखों बच्चे सरकारी नौकरी का सपना लेकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन हेमंत सरकार ने उनके सपने को कुचल दिया है। जेएसएससी-सीजीएल जैसी बड़ी परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। इसका मतलब है कि पूरी भर्ती मशीनरी ही फेल हो गई है। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ जो भर्तियां हो रही हैं, उन्हें ही रद्द करना पड़ रहा है। इससे बड़ा मजाक युवाओं के साथ और क्या हो सकता है? छात्रों ने 24 दिन तक धूप, बारिश और लाठी-डंडे सहे, तब जाकर सरकार को अक्ल आई। अगर छात्र नहीं जागते तो सरकार आज भी टीडीपीएल के जरिए परीक्षाएं करवाती रहती। सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती। जनता सब देख रही है। आपने 12 साल तक युवाओं को ठगा है। अब एक फैसले से आपकी छवि साफ नहीं होगी।

अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म बची है तो दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करे, निजी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करे और एक पारदर्शी भर्ती बोर्ड बनाए। नहीं तो याद रखिएगा, जिस छात्र शक्ति ने आज आपको झुकाया है, वही छात्र शक्ति अगले चुनाव में आपको सत्ता से भी उखाड़ फेंकेगी। झारखंड के युवाओं ने साबित कर दिया है कि अगर सरकार सो जाए तो सड़क ही संसद बन जाती है। अब गेंद सरकार के पाले में है। या तो वह सुधार करे या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहे।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

क्लिक करते ही खाली हो जाएगा खाता, डिजिटल ठगी के नए हथियार

तकनीक ने जीवन बदल दिया है, लेकिन उसी तकनीक को हथियार बनाकर साइबर अपराधी हर दिन नए जाल बिछा रहे हैं। भोपाल में हुई एक राष्ट्रीय कार्यशाला में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने साफ कहा कि अब अपराध पहले जैसा नहीं रहा। यह संगठित गिरोहों का खेल बन गया है और हर क्लिक पर आपका डेटा खतरे में है। विशेषज्ञों ने चेताया कि डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सुरक्षा है।

फर्जी लिंक, डीपफेक वीडियो, एआई से बनी आवाज और सोशल मीडिया के जरिए ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकार युवा और बुजुर्ग हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार और पुलिस अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकती। जब तक हर नागरिक जागरूक नहीं होगा, तब तक ठगी रोकना मुश्किल है।

पहले पासवर्ड चोरी, अब दिमाग की चोरी। पहले साइबर अपराधी सिर्फ हैकिंग करते थे, अब वे मनोविज्ञान से खेलते हैं। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अपराधी दोस्त बनकर बात करते हैं, भरोसा जीतते हैं और फिर ओटीपी, बैंक डिटेल या पैसे मांग लेते हैं।

व्हाट्सएप पर रिश्तेदार बनकर मदद मांगना, फर्जी लॉटरी और गिफ्ट का लालच देना, नौकरी के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस लेना और कस्टमर केयर बनकर कार्ड की जानकारी लेना अब आम बात हो गई है।

सबसे खतरनाक नया तरीका है डीपफेक और वॉइस क्लोनिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपराधी किसी अधिकारी या परिवार के सदस्य का चेहरा और आवाज कॉपी कर लेते हैं। फिर वीडियो कॉल करके तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। देखने और सुनने में सब असली लगता है, इसलिए लोग झांसे में आ जाते हैं।

आज के समय में डेटा सबसे महंगा है। आपका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की जानकारी डार्क वेब पर बोली लगाकर बेची जाती है। एक बार लीक होने के बाद यह जानकारी बार-बार इस्तेमाल होती है। इसीलिए सार्वजनिक वाई-फाई से बचें, अनजान ऐप को परमिशन न दें और पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें। हर अकाउंट में दो-चरणीय सुरक्षा जरूर चालू करें, ताकि पासवर्ड लीक होने के बाद भी खाता सुरक्षित रहे। कंपनियों और सरकारी विभागों को भी अपने सर्वर मजबूत करने होंगे, क्योंकि एक बार किसी बड़े पोर्टल का डेटा लीक हुआ तो करोड़ों लोगों की जानकारी खतरे में आ सकती है।

कार्यशाला में आंकड़े दिखाए गए कि साइबर ठगी के दो बड़े शिकार युवा और बुजुर्ग हैं। युवा ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए फर्जी ऑफर और फर्जी प्रोफाइल के झांसे में आ जाते हैं। वहीं बुजुर्ग डिजिटल लेनदेन को पूरी तरह नहीं समझते और घबराहट में ओटीपी बता देते हैं। कई बार बेटे के नाम पर कॉल आती है और वे तुरंत पैसे भेज देते हैं।

छोटे व्यापारी भी निशाने पर हैं। उन्हें व्हाट्सएप पर फर्जी ऑर्डर और क्यूआर कोड भेजकर भुगतान के नाम पर ठगा जा रहा है।

सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए 1930 हेल्पलाइन शुरू की है। देशभर में साइबर थाने खोले गए हैं और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कानून के साथ गति भी जरूरी है। साइबर अपराधी एक राज्य से बैठकर दूसरे राज्य के लोगों को ठगते हैं। कई बार दूसरे देश से ऑपरेट करते हैं, इसलिए जांच में समय लगता है। पुलिस को भी नई तकनीक की ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वह अपराधियों से दो कदम आगे रहे।

स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर साइबर शिक्षा अनिवार्य की जाए, ताकि बच्चे शुरू से ही डिजिटल खतरों को समझें। पांच सबसे बड़ी गलतियां हैं - किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करना, कॉल पर ओटीपी और सीवीवी नंबर बताना, सोशल मीडिया पर अपनी पूरी निजी जानकारी सार्वजनिक करना, मुफ्त में कुछ पाने के लालच में फर्जी ऐप डाउनलोड करना और ठगी होने के बाद डरकर शिकायत न करना।

अगर आपके साथ ठगी हो जाए तो पहले 1930 पर कॉल करें, फिर बैंक को तुरंत सूचना दें और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। समय पर रिपोर्ट करने से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

आगे साइबर अपराध और खतरनाक होंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल अपराधी भी करेंगे। इसलिए सरकार को साइबर सुरक्षा का बजट बढ़ाना होगा और शोध को बढ़ावा देना होगा। साइबर सुरक्षा अब सिर्फ आईटी विभाग का काम नहीं रही, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गई है। उद्योग जगत को भी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना होगा।

बड़ा संदेश यही है कि तकनीक बुरी नहीं है, इस्तेमाल गलत हो सकता है। हम जैसे सड़क पर ट्रैफिक नियम मानते हैं, वैसे ही इंटरनेट के नियम भी मानने होंगे। माता-पिता बच्चों को बताएं कि ऑनलाइन दोस्ती में सावधानी रखें। शिक्षक छात्रों को साइबर नैतिकता सिखाएं और हम सब मिलकर संदिग्ध मैसेज को फॉरवर्ड करने के बजाय रिपोर्ट करें।

डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा, जब डिजिटल नागरिक सुरक्षित होगा। सरकार की योजनाएं और पुलिस की मेहनत तभी रंग लाएंगी, जब आम लोग खुद सतर्क रहेंगे। एक बार फिर याद रखें कि आपकी उंगली का एक क्लिक आपको करोड़पति भी बना सकता है और कंगाल भी। इसलिए फोन उठाने से पहले सोचें, लिंक खोलने से पहले जांचें और कोई भी जानकारी देने से पहले रुकें। क्योंकि अब चोर ताला नहीं तोड़ता, वह आपका पासवर्ड मांगता है और आप खुद ही दरवाजा खोल देते हैं।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)